फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 105 प्रभात जयपुर, बुधवार 16 नवम्बर , 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

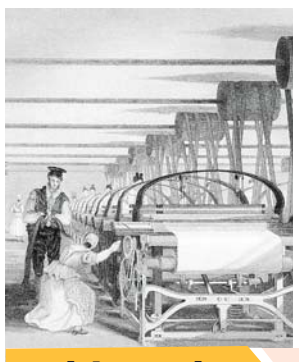

This Fork In Time...

The Industrial Revolution changed the time of day from sunrise to sunset, to shift start and knock off in the factory.

Manipulate Stress Response

Why Do Batteries Lose Charge? Although we take them for granted, batteries are technological miracle

प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने अखबारों की स्वतंत्रता के पक्ष में भारी वार किया राजस्थान सरकार पर

प्रेस काउन्सिल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रेस के बारे में व्यक्त किये गए उद्गारों के प्रति ''भारी नाराज़गी'' जताई। गहलोत ने अखबारों को, दिसम्बर 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली धमकी दी थी कि, सरकार उन अखबारों को ही विज्ञापन जारी करेगी जो सरकार की रीति-नीति व कामकाज को पूरे विश्वास से प्रसारित व प्रचारित करते हैं। गहलोत ने अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिये, राष्ट्रदूत को टारगैट किया। कई महीनों राष्ट्रदूत के दफ्तर में पुलिस भेजी, कम्प्यूटर ''सीज़'' करने की धमकी के साथ तथा लगभग तीन साल विज्ञापन बंद कर दिये। प्रेस काउन्सिल ने सरकार की अखबार को डराने की इस प्रवृत्ति की तो निन्दा की है, साथ में मूल प्रश्न उठाया है कि, सरकारी कोष किसी भी राजनीतिज्ञ की सम्पत्ति नहीं है, सरकारी विज्ञापन जारी करने की भी एक घोषित सरकारी नीति होना कानूनन जरूरी है, और उसका निष्पक्षता से क्रियान्वयन होना भी जरूरी है। प्रेस काउन्सिल की दृष्टि में गहलोत सरकार इन स्थापित मापदण्डों में खरी नहीं उतरी। अतः प्रेस काउन्सिल ने ''एक्स्ट्रीम डिस्प्लैज़र'' लिखित में व्यक्त किया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) ने मंगलवार को इस बात के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लताड़ा कि उन्होंने जनवरी 2020, अर्थात् पिछले करीब तीन साल से अपने अनुकूल खबरें प्रकाशित नहीं करने के कारण राज्य के प्रमुख हिन्दी दैनिक राष्ट्रदूत को राज्य सरकार के विज्ञापन देना बंद कर रखा है। पी.सी.आई. ने प्रथम दृष्टया उन्हें विज्ञापन जारी किये जाने के मामले में इस समाचार पत्र के प्रति भेदभाव बरतने का दोषी ठहराया।

प्रैस काउंसिल के इस ऐतिहासिक फैसले से अन्य ऐसे बहुत से अखबारों को सरकार के दमन के खिलाफ संघर्ष में मदद मिलेगी, जो, यदि सरकार की राजनैतिक सोच का अनुसरण नहीं करते हैं तो उन्हें दबाने के लिए उनके विज्ञापनों में भारी कटौती कर दी जाती है, इस प्रकार कई अखबार तो बंद होने को मजबूर कर दिए जाते हैं।

पी.सी.आई. ने राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 16 दिसम्बर, 2019 को जयपुर की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में दिये गये इस विवादास्पद बयान पर ''कड़ी नाराज़गी'' व्यक्त की कि ''केवल उन्हीं अखबारों को सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, जो सरकारी स्कीमों का प्रचार-प्रसार पूरे मनोयोग के साथ करेंगे।''

पी.सी.आई. ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुये, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया तथा कहा कि, वह अशोक गहलोत की इस अनुचित टिप्पणी का स्पष्टीकरण दे। पी.सी.आई. ने मंगलवार को एक अंदरूनी जाँच रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि ''मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह बयान कि, विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों को जारी किये जायेंगे, जो सरकारी स्कीमों का प्रचार-प्रसार करेंगे, एक ऐसा कदम है जिससे जनता के हित तथा उसके लिये महत्वपूर्ण समाचारों का प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार रूक जाने की संभावना है। अगर ऐसे बयानों पर अमल होता है तो इससे उन अखबारों की आर्थिक जीवन क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है, जिन्हें संभवतया राजनैतिक कारणों से विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे, तथा इसके चलते, जनता के हित तथा उसके लिये महत्वपूर्ण समाचारों के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करने की अखबरों की क्षमता पंगु हो जायेगी।''

''राष्ट्रदूत'' राजस्थान का तीसरा सर्वाधिक सर्कुलेशन वाला दैनिक है जिसके 8 संस्करण प्रकाशित होते हैं, लेकिन सरकारी विभागों, बोर्डों तथा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

122 सांसदों और विधायकों पर ई.डी. का शिकंजा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। एनफोर्समेंन्ट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 51 सांसदों और 71 विधायकों के विरूद्ध दर्ज किए गए मनी लॉंड्रिंग केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इनमें से कितने वर्तमान सांसद और विधायक हैं और कितने पूर्व सांसद या विधायक हैं।

सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने भी वर्तमान तथा पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ 121 केस दायर किए थे। उनमें से 51 सांसद थे, जिनमें 15 तो निवर्तमान हैं, जबकि

- **ई.डी. ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दी है। जिसके अनुसार 51 सांसद और 71 विधायकों, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, पर मनी लॉडरिंग का केस है।**

पांच अन्य का निधन हो चुका है। जहां तक विधायकों की बात है, सी.बी.आई. ने 112 विधायकों की सूची दी थी, जिनमें 34 निवर्तमान तथा 78 पूर्व विधायक हैं, जबकि 9 अन्य का निधन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर सांसदों-विधायकों के खिलाफ चल रहे लंबित केसों के संबंध में दोनों एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी। उपाध्याय की याचिका में इन केसों पर सुनवाई जल्दी निबटाने की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने एक अलग रिपोर्ट में कानून निर्माताओं के केसों की सुनवाई में हो रहे भारी बिलम्ब के बारे में बताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई केस तो पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

राहुल संभालेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। कांग्रेस ने मंगलवार को इस असमंजस की स्थिति को समाप्त कर दिया कि राहुल, ''भारत जोड़ो यात्रा'' में व्यस्त होने के कारण गुजरात में चुनाव-प्रचार करेंगे या नहीं।

राहुल का नाम प्रथम चरण के मतदान वाले चुनाव क्षेत्रों के लिये जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मौजूद है।

उनके प्रचार-अभियान की तारीखें अभी नहीं बताई गई हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में उनके गहन प्रचार-अभियान से पार्टी को लाभ हुआ था।

- **भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्तता की वजह से राहुल गांधी के गुजरात के चुनाव प्रचार करने पर व्याप्त तमाम संशय को दूर कर दिया गया है। गुजरात में ए.आई.सी.सी. के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल टॉप पर हैं।**

उनकी माँ तथा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उनकी बहिन प्रियंका गांधी वाड्रा भी स्टार प्रचारकों की सूची में हैं।

प्रचार-अभियान का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे।

स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल प्रमुख नेता हैं- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा कमलनाथ, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, ए.आई.सी.सी. महासचिव शक्ति सिह गोहिल तथा तारिक अनवर, अर्जुन मिडिवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, जिग्नेश मेवानी तथा गुजरात-प्रभारी रघु शर्मा।

'पी.सी.आई. ''सैंसर बोर्ड'' नहीं है गहलोत साहब'

सरकार ने पी.सी.आई. में यह दलील दी थी कि, पी.सी.आई. केवल अखबारों और न्यूज़ एजेंसी को सैंसर करने के लिए बनाई गई है

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 15 नवम्बर। अशोक गहलोत सरकार द्वारा मीडिया में स्वतंत्र अखबारों और पत्रकारों की आवाज पर ताला लगाने की कोशिशों और सामंतवादी रवैये का ''प्रैस काउन्सिल ऑफ इंडिया'' (पी.सी.आई.) ने कठोर शब्दों में आलोचना की है। पी.सी.आई. ने 15 नवम्बर को जारी अपने आदेश में स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मीडिया में ही दिये एक बयान कि '' हमारी (अशोक गहलोत सरकार) न्यूज छापोगे तो ही विज्ञापन मिलेंगे'' पर अत्यंत नाराजगी भी जताई है।

- **राष्ट्रदूत के जवाब और पी.सी.आई. के आदेश में प्रस्तुत एतिहासिक तथ्यों ने राज्य सरकार की इस दलील की हवा निकाल दी।**

इस प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 दिसम्बर, 2019 को सीएम आवास पर लाइव प्रैस कॉन्फेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मीडिया को खुली धमकी देते हुए कहा था कि सरकार उन्हीं अखबारों को विज्ञापन देगी, जो सरकार की रीति-नीति के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर लिखेंगे। इस घटना को एक कमज़ोर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एमेज़ॉन एक बार फिर संघ के निशाने पर

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। विशाल ई-कॉमर्स कंपनी एमेज़ॉन को आर.एस.एस. ने पुनः निशाने पर लिया है। संघ से सम्बद्ध पत्रिका ''ऑर्गनाइज़र'' ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह देश के पूर्वोत्तर भाग में धार्मिक धर्मान्तरण के लिये धन उपलब्ध करा रही है। आर.एस.एस. से जुड़े संगठन पिछले कुछ समय से अमेज़ॉन को निशाना बना रहे हैं। इससे पूर्व, ऑर्गनाइज़र ने एमेज़ॉन पर आरोप लगाया था कि कंपनी खुदरा बाजार पर कब्जा करके छोटे व्यापारियों/दुकानदारों को जबरदस्त नुकसान पहुँचा रही है। ज्ञातव्य है कि यह समुदाय संघ परिवार तथा भाजपा का परम्परागत समर्थक रहा है। पिछले वर्ष

- **संघ का आरोप है, एमेज़ॉन नॉर्थ-ईस्ट में धर्म परिवर्तन के अभियान को फाइनैंस कर रहा है।**

सितम्बर में, ऑर्गनाइज़र के हिन्दी संस्करण ''पांचजन्य'' ने कंपनी पर ईसाई संगठनों की फंडिग में लिप्त होने का आरोप लगाते हुये, कथित रूप से भ्रष्ट करतूतों के मामले में एमेज़ॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी के समान बताया था। पिछले वर्ष दिसम्बर में, स्वदेशी जागरण मंच ने एक प्रस्ताव पारित कर माँग की थी कि एमेज़ॉन तथा फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स फर्मों को दी गई तमाम अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियाँ वापस ले ली जायें। एस.जे.एम. ने कहा था कि इन फर्मों द्वारा दिये जाने वाले डिस्काउन्ट आस पास की किराने की दुकानों पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। सितम्बर की इससे पूर्व की रिपोर्ट में, ऑर्गनाइज़र ने आरोप लगाया था कि ''आल इंडिया मिशन (ए.आई.एम.), जो एमेज़ॉन से जुड़ा हुआ बताया जाता है, ने झारखंड में दो मोर्चे खोल रखे हैं तथा इसके संस्थापक ''भारत एवं केन्द्र सरकार को बदनाम करने का निष्ठुर अभियान'' चला रहे हैं।''

एमेज़ॉन पर यह नया हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब कंपनी की आय घट रही है तथा रिपोर्ट बता रही हैं कि एमेज़ॉन मोटे तौर पर अपने 10,000 कर्मचारियों की छँटनी की योजना बना रही है तथा छँटनी की यह प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरु होने की संभावना है। अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरदारशहर से भाजपा ने अशोक पिंचा को उतारा

जयपुर, 15 नवंबर। भाजपा ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए अशोक कुमार पिंचा पर ही एक बार फिर भरोसा जताया है। पिंचा वर्ष 2018 में भी पार्टी के प्रत्याशी रहे थे। भाजपा

- **अशोक पिंचा अब तक चार बार चुनाव हार चुके हैं ऐसे में उन्हें टिकट दिए जाने से भाजपा में अटकलों का दौर शुरू हो गया है।**

की केन्द्रीय चुनाव समिति ने अशोक कुमार पिंचा को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टी.आर.एस. व भाजपा में नयी होड़ शुरू हुई तेलंगाना में

भाजपा ई.डी. का इस्तेमाल कर रही है, तो टी.आर.एस. अपने जी.एस.टी. स्टाफ का

- **इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य है, विधायकों को डरा धमका कर या प्रलोभन देकर अपने खेमे में लाना।**
- **यह स्पर्धा शुरू हुई, भाजपा के मुनुगोडे के उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन से, भाजपा बहुत कम वोटों से हारी यह उपचुनाव।**

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। तेलंगाना में चल रही राजनैतिक लड़ाई में, सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति भी विधायक एवं नेताओं को छीनने के मामले में अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा से कम नहीं पड़ रहीं है। नेताओं को चुराने का उद्देश्य, अगले वर्ष दिसम्बर के अन्त में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक ऐसा वातावरण बना देना है कि संबंधित पार्टी नेताओं की पसंदीदा पार्टी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ टी.आर.एस., भाजपा की नकल करते हुये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी (भाजपा) भ्रष्ट है। टी.आर.एस. यह आरोप लगा रही है कि भाजपा उसके विधायकों को खरीदने के लिये पैसा काम में ले रही है। बताया जाता है कि भाजपा के नजदीकी लोगों द्वारा अपने चार विधायकों को लुभाये जाने के आरोपों की जाँच की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव स्वयं कर रहे हैं।

और तो और, तेलंगाना सरकार के जी.एस.टी. अधिकारियों ने भी भाजपा नेता कोमाति रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बेटे के व्यावसायिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। मुनुगोडे विधानसभा उपचुनावों, जिनमें भाजपा मामूली अंतर से हारी थी, के चन्द दिन बाद, राज्य सरकार के जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को भाजपा प्रत्याशी कोमाति रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बेटे संकीर्त रेड्डी के पोस्ट बंजारा हिल्स-स्थित व्यावसायिक परिसरों पर छापे मारे थे। जी.एस.टी. जाँचकर्ताओं की 20 टीमों, जिनमें करीब 150 अधिकारी थे, ने भाजपा नेता के बेटे द्वारा संचालित सुश्री इन्फ्रा एंड माइनिंग के परिसरों पर छापे मारे थे। ये छापे टी.आर.एस. की एक शिकायत पर मारे गये थे, जिसमें यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्ततोगत्वा रिपब्लिकन पार्टी में ट्रम्प का ''चैलेंजर'' उभरा, 2024 के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में

फ्लोरिडा के गवर्नर के हाल ही में हुए चुनाव में रॉन डीसैन्टिस न केवल गवर्नरी जीते, बल्कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रम्प के आगे निकले

- **नवीनतम सर्वे के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी के केवल 35 प्रतिशत लोग ट्रम्प को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि डीसैन्टिस के पक्ष में 42 प्रतिशत रिपब्लिकन हैं।**
- **महिलाओं में भी ट्रम्प का समर्थन करने वाली लेडीज़ केवल 15 प्रतिशत हैं, जबकि डीसैन्टिस को 22 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन प्राप्त है।**
- **डीसैन्टिस की बढ़ती लोकप्रियता से ट्रम्प, स्वाभाविक ही है, ज्यादा खुश नहीं हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि, डीसैन्टिस के पास ''लो-अप्रूवल'' (नगण्य समर्थन) व ''नो मनी'' (पैसा नहीं) है।**

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैन्टिस घबराहट पैदा कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका में वर्ष 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव में वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की दौड़ में अगुवा बन कर उभरे हैं। एक नया सर्वेक्षण दर्शाता है कि राष्ट्रपति के लिए अगले चुनाव में डैमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के सामने डीसैन्टिस को रिपब्लिकन पार्टी के चुनौतीकर्ता के रूप में चुने जाने की संभावनाएं स्पष्ट लग रही हैं।

यूजीओवी अमेरिका का एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि पिछले हफ्ते हुए मध्यावधि चुनाव में, फ्लोरिडा के गवर्नर ने ग्राण्ड ओल्ड पार्टी (जी.ओ.पी.) रिपबल्किन्स की ओर एकतरफा जीत दर्ज कर स्वयं को सुपरस्टार साबित किया है। चुनाव से प्रकट होता है कि डीसैन्टिस पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को 7 प्रतिशत पीछे धकेल रहे हैं।

यूजीओवी अमेरिका सर्वेक्षण ने 15 सौ वोटर्स से पूछा कि वे वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में किसे रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेंगे। बियालीस प्रतिशत रिपब्लिकन वोटर्स ने इसके लिए डीसैन्टिस को चुना जबकि 35 प्रतिशत रिपब्लिकन वोटर्स ने ट्रम्प को चुना।

रिपब्लिकन्स के 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वोटर्स में डीसैन्टिस पूर्व राष्ट्रपति की तुलना में अधिक लोकप्रिय साबित हुए हैं। इनमें 16 प्रतिशत वोटर्स गवर्नर डीसैन्टिस को प्राथमिकता देते हैं। विशेष यह भी है कि डीसैन्टिस ने महिलाओं के 22 प्रतिशत वोट प्राप्त किए, जबकि ट्रम्प को उनकी तुलना में महिलाओं के सिर्फ 15 प्रतिशत ही मत प्राप्त हुए।

मध्यावधि चुनावों के बाद ट्रम्प डिसान्टिस की आलोचना करते रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव में उनका समर्थन किया, जबकि ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ''ट्रूथ सोशल'' पर गवर्नर रॉन को ''डिसैक्टिमॉन्यस'' बताते हुए कहा था कि वर्ष 2018 में हुए गवर्नर पद के चुनाव में उन्होंने डैमोक्रेट प्रत्याशी एन्ड्रयू गिलम के विरूद्ध जीत दर्ज करने में डीसैन्टिस की मदद की थी।

ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प ने यह भी कहा कि ''रॉन के प्रति जनता का समर्थन बहुत कम था, उनका चुनावी करियर खराब था और उनके पास धन नहीं था, लेकिन रॉन ने मुझसे कहा कि यदि मैं उनका समर्थन करूं तो वह जीत सकते हैं।''

इस बीच फॉक्स न्यूज की रायशुमारी स्तम्भकार लिज़ पीक ने पूर्व राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव का ''बिगैस्ट लूज़र'' बताते हुए उनकी भर्त्सना की और कहा कि यदि वह वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो वह रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को और नुकसान पहुंचाएंगे।

पीक ने लिखा कि ''वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकलन पार्टी का नामांकन प्राप्त करने में ट्रम्प कोई भी तिकड़म आजमाने को तत्पर रहेंगे और ''यदि वह ऐसा करेंगे तो वे अपनी ही पार्टी में अपने प्रति नफरत और घ्रणा को और मजबूत करेंगे तथा ऐसा करके वह डैमोक्रेट्स को परास्त करने की रिपब्लिकन्स की संभावनाओं को एक बार धूमिल कर देंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)